



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51 संख्या: 133

प्रभात

कोटा, बुधवार 25 फरवरी, 2026

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

भाजपा का बंगाल की संस्कृति से जुड़ने का प्रयास, इस बार सफल हो सकता है

प्र.मंत्री मोदी की, “जय माँ काली” का उद्घोष करके बंगाल के “ईथॉस” से जुड़ने की कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है

–श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए भाजपा की रणनीतिक पुनर्निर्धारण और बदली हुई कार्यशैली, जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जाँय माँ काली” के आ आन से हुआ, महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पिछले 2021 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने टैगोर जैसी दाढ़ी रखी थी, लेकिन “जय श्री राम” नारे के नवाचार के माध्यम से राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक भावना से जुड़ने में वे सफल नहीं हो पाए थे। हाल के सप्ताहों में भी गुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं ने मोदी और भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे बंगाल की सोच और भावनाओं से तालमेल बिटाने में असफल हैं। उदाहरण के तौर पर, टीएमसी ने रामकृष्ण परमहंस को “स्वामी

- अब तक कई कोशिशों के बावजूद भाजपा व मोदी, बाहर का होने की छाप को नहीं धो पाए थे, बंगाल में।
- छोटी-छोटी ब्रुटियाँ, जैसे, मोदी जी द्वारा रामकृष्ण परमहंस को स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहना, काफी खला बंगाल के निवासियों को, क्योंकि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को भगवान स्वरूप माना जाता है तथा अन्य स्वामी, जैसे स्वामी विवेकानंद आदि उनके शिष्य थे।
- इसी प्रकार, प्र.मंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय को “बंकिम दा” कह कर संबोधित करने पर भी बंगाली निवासी कुछ अटपटा सा महसूस कर रहे थे। इसी तरह प्र.मंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को आसामवासी बताना भी बंगालियों की दृष्टि से महान ब्रुटि थी।
- पर, अब प्र.मंत्री मोदी द्वारा, बंगाल की जनता का “जाँय माँ काली” कहकर, अभिवादन करने को सभी सराहनीय व सफल प्रयास बता रहे हैं और इससे प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा, बंगाल में बाहरी होने की छाप धो सकेंगे।

रामकृष्ण परमहंस” कहकर संबोधित करने पर मोदी की आलोचना की। एक बंगाल पर्यवेक्षक ने कहा, “उन्हें पता होना चाहिए था कि परमहंस को बंगाल

में भगवान के रूप में पूजा जाता है, और स्वामी (जैसे स्वामी विवेकानन्द) उनके शिष्य थे।” कुछ दिन पहले, टीएमसी सांसदों

ने लोकसभा में तब काफी हंगामा किया था, जब प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को “बंकिम दा” कहकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“जय श्री राम” से भाजपा “जय माँ काली” पर शिफ्ट हुई बंगाल में

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। भारतीय राजनीति की जटिल बुनावट में सांस्कृतिक प्रतीकों के इर्द-गिर्द बुनी गई कुछ कथाएँ सबसे जीवंत और अक्सर सबसे विवादित, धाराओं में से एक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अभियान में हाल ही में “जय माँ काली” का

कांग्रेस ने द्रमुक से 41 सीटें मांगीं

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। कांग्रेस के महासचिव के.सी वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात के एक दिन बाद, डीएमके (द्रमुक) संसदीय दल की नेता कनिमोई करुणानिधि ने सोमवार को अपने आवास पर कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर के साथ सीट बंटवारे को लेकर आगे की चर्चा की। हालाँकि किसी भी नेता ने अधिकारिक रूप से बातचीत के विवरण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों

- कांग्रेस का कहना है, उसने 2016 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर, द्रमुक उसे वही 25 सीटें देना चाहती है, जो कांग्रेस को 2021 में दी गई थीं।

के अनुसार, कांग्रेस ने द्रमुक को राज्यसभा की एक सीट के अपूर्व वादे की याद दिलाई है, और ऐसी संभावना है कि द्रमुक इस मांग को मान लेगी। लेकिन जहाँ कांग्रेस 41 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, जिन पर वह 2016 में चुनाव लड़ी थी, वहाँ द्रमुक 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दी गई 25 सीटों के प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। शीर्ष सूत्रों का कहना है कि द्रमुक कांग्रेस को दो या तीन अतिरिक्त सीटों से अधिक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक सूत्र ने कहा, “अधिकतम 26 या 27, लेकिन इससे ज्यादा देना हमारे लिए संभव नहीं है।”

- भाजपा का “जय श्री राम” के मंत्र की प्रतिध्वनि उत्तर व पश्चिम भारत में तो खूब लोकप्रिय रही है, पर, बंगाल के लिए “जय माँ काली” के नारे की “इमोशनल अपील” (भावनात्मक आकर्षण) को जनप्रिय माना गया।

उद्घोष करना भाजपा के संदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह परिवर्तन न केवल पहले के “जय श्री राम” नारे, जो मुख्यतः उत्तर और पश्चिमी राज्यों में अधिक प्रभावी रहा, से दूरी बनाता है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीति को भी दर्शाता है, जिसके तहत भाजपा पश्चिम बंगाल में लंबे समय से उस पर लगे “बाहरी” होने के ठप्पे को हटाने का प्रयास कर रही है। माँ काली और माँ दुर्गा का आ आन बंगाल की सामूहिक चेतना में गहराई से गुंजाता रहता है। ये देवियाँ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं, और, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक बनकर, विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध किले की तरह खड़ी रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंगाल के मतदाताओं को लिखे गए पत्रों में प्रयुक्त

भाषा इस बात को रेखांकित करती है कि भाजपा स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में स्वयं को स्थापित करने का गंभीर प्रयास कर रही है, ताकि उन मतदाताओं के बीच अपनापन पैदा किया जा सके, जो पहले पार्टी को अलगाव की दृष्टि से देखते रहे होंगे। भाजपा नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोलकाता में महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए इस सांस्कृतिक सामंजस्य पर और विस्तार से प्रकाश डाला।

महिलाओं से “अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जगाने” का आ आन करते हुए, गुप्ता ने न केवल महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, बल्कि सामाजिक बुराईयों के खिलाफ संघर्ष में देवियों के गहरे निहित महत्व को भी रेखांकित किया।

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी की नागरिकता रद्द करेगा कैनडा

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। कैनडा सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहज्जुब हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की 26

- कैनडा के प्र.मंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा से पूर्व उठाए जा रहे इस कदम को दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

फरवरी को होने वाली भारत यात्रा से पहले उठाया गया है, क्योंकि ओटावा नई दिल्ली के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केरल अब बनेगा “केरलम्”

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी, केरल विधानसभा ने आधिकारिक अभिलेखों में राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केरल का नाम बदलकर “केरलम्” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य विधानसभा पहले ही आधिकारिक अभिलेखों में नाम परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति

- केरल विधानसभा ने राज्य का आधिकारिक रूप से नाम बदलने के लिए विधेयक पारित कर दिया है।

के बाद, भारत के राष्ट्रपति “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत राज्य विधानमंडल के विचारार्थ केरल विधानसभा को भेजेंगे।

केरल राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त होने के बाद, केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘एसआईआर जल्दी कराने के लिए सिविल जजों को भी तैनात कर सकते हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया और कहा कि सिविल जज तीन साल के अनुभवी होने चाहिए

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है।

अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया (ईसीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच भरोसे की कमी है। कोर्ट ने 20 फरवरी को एसआईआर के सुचारु संचालन के लिए जिला जज और अतिरिक्त जिला जज, यहां तक कि सेवानिवृत्त जजों की भी तैनाती का आदेश दिया था।

इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट भेजकर बताया कि यह काम बहुत

रूस की “इकॉनमी” क्या “डैथ ज़ोन” में पहुँच गई है?

माउण्ट एवरेस्ट की चढ़ाई में 25,000 फीट के बाद एक भूखण्ड आता है जिसे “डैथ ज़ोन” कहा जाता है, जहाँ सर्वाधिक पर्वतारोहियों की मृत्यु होती है

–अंजन राय–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 24 फरवरी। रूसी अर्थव्यवस्था उस स्थिति में पहुँच गई है, जिसे ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ाई की भाषा में “डैथ ज़ोन” कहा जाता है। एवरेस्ट की चोटी पर जाते समय 25,000 फीट से ऊपर का इलाका आता है, जहाँ चोटी पर पहुँचने की कोशिश के दौरान सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इस ऊंचाई पर मानव शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है, उतनी उसकी भरपाई नहीं कर पाता। जब तक व्यक्ति असामान्य ऊँचाई को जल्दी से नहीं छोड़ता, मृत्यु लगभग तय हो जाती है।

लंदन से निकलने वाली एक प्रसिद्ध और सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका, द लंदन इकॉनॉमिस्ट, ने एक विशेषज्ञ लेख प्रकाशित किया है। इसमें तर्क दिया गया है कि पिछले चार वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रूसी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुँच गई है, जहाँ वह युद्ध के लिए जरूरत से ज्यादा संसाधन खर्च कर रही है, जो उसकी असली क्षमता से भी अधिक हैं। अर्थ व्यवस्था अपने उत्पादन क्षेत्रों को कमजोर कर रही है और वहाँ से

- “डैथ ज़ोन” में मानव शरीर, जितनी ऊर्जा उपयोग में लाता है, उतना उसका रिफ्लेसमेंट संभव नहीं हो पाता, अतः, पर्वतारोही अपनी अपनी जान गाँवाँ बैठता है, अगर तुरंत अपनी रिहाइश का स्थान नहीं बदलता।

- यह ही स्थिति रूस की इकॉनमी की हो रही है, जानकार विशेषज्ञों के अनुसार।

- यूक्रेन युद्ध के कारण सेना की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा है रूस ने तथा अधिकतम औद्योगिक उत्पादन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेना की जरूरतें पूरी करने में लगा है और साधारण रोजमर्रा की आवश्यकताएँ पीछे से पीछे खिसकती जा रही हैं।

- जितनी देर रूस की इकॉनमी, इस “डैथ ज़ोन” में रहेगी, उतना ही अधिक मुश्किल हो जाएगा, इस “डैथ ज़ोन” से बाहर निकलना।

संसाधन खींचकर रक्षा उद्योगों में लगा रही है, ऐसे सामान बनाने के लिए, जो तुरंत युद्ध में नष्ट हो जाते हैं। अतः यह ऐसा है, जैसे, अर्थव्यवस्था उत्पादन, आय और विकास के अच्छे चक्र में आने के बजाय, तेज़ी से खुद को ही खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। यह आकलन वॉशिंगटन के कार्नेगी रूस यूरेशिया सेंटर की

एलेक्ज़ेंड्रा प्रोकोपेंको का है। उनका कहना है कि रूसी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या “नकारात्मक संतुलन” है, यानी वह खुद को किसी तरह संभाले हुए है, लेकिन साथ ही अपने भविष्य की क्षमता को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। प्रोकोपेंको की विश्लेषण के अनुसार, रूसी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार में भरोसे की भारी कमी है। कोर्ट ने इससे पहले 20 फरवरी को एसआईआर के संचालन के लिए जिला जज, अतिरिक्त जिला जज व सेवानिवृत्त जजों की तैनाती का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की तैनाती का आदेश भी दिया है, ताकि एसआईआर कायावद में तेजी लाई जा सके।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर उड़ीसा व झारखंड के सेवारत या सेवानिवृत्त जजों की मदद ली जा सकती हैं। इनकी यात्रा, रहने व खाने का खर्च चुनाव आयोग उठाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संशोधित मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद पूरक सुचियाँ जारी की जा सकती हैं तथा पूरक सूची में शामिल मतदाताओं को 28 फरवरी को जारी की गई संशोधित मतदाता सूची में शामिल माना जाएगा।

बड़ा है, 250 न्यायिक अधिकारियों को लगभग 50 लाख मतदाताओं के मामलों का फैसला करना है, जो “लॉजिकल डिफ़िफ़ेंस” और “अनमैड” श्रेणी में आते हैं। अनुमान लगाया गया कि यदि हर

जज रोज 250 मामलों का निपटारा करें, तो भी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 80 दिन लगेंगे। इसी को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और

जस्टिस विपिन पंचोली की पीठ ने आज सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दे दी, ताकि काम युद्ध स्तर पर किया जा सके। पीठ ने कहा, “इस तथ्य और समय की कमी को देखते हुए हमें लगता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मैकडॉनल्ड्स के एमडी, अभिनेता रणवीर व कार्तिक आर्यन को नोटिस

जयपुर, 24 फरवरी। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने शहर के गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में हानिकारक तेल में खाद्य सामग्री बनाने से जुड़े मामले में मैकडॉनल्ड्स के एमडी

- जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर- द्वितीय ने दूषित तेल में खाद्य सामग्री बनाने पर 23 मार्च तक जवाब मांगा।

राजीव रंजन, ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह व कार्तिक आर्यन सहित, प्रबंधक संभव भारद्वाज को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने इनसे 23 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवाद पर दिए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)